सौर ऊर्जा के विकास पर खास जोर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय परियोजना स्थापित हो रही है। इसके तहत पारेषण तंत्र के निर्माण के लिए 1554 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह सोलर पावर पार्क का विकास व पीएम कुसुम योजना के तहत निजी ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन पर जोर दिया गया है। उप्र. राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए भी 45 करोड़ दिए गए हैं।

1554 करोड़ रुपये बुंदेलखंड सौर ऊर्जा परियोजना के लिए दिए गए

वाराणसी व आगरा में बनेगी साइंस सिटी

सरकार ने वाराणसी एवं आगरा में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था की है। इसके तहत स्थापना के लिए दो-दो करोड़ एवं मशीन व उपकरणों के लिए 13-13 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने के लिए दिए 15.75 करोड़

प्रदेश में बिजली सुधार एवं पहले से चल रही योजनाएं चलती रहेंगी। विभाग को 47899 करोड़ का बजट मिला है। पहले से चल रही संशोधित वितरण योजना (रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम) पहले की तरह चलती रहेगी। बिजली उत्पादन के लिए चल रही अनपरा अ, अनपरा ब के लिए 898 लाख की व्यवस्था की गई है। इसी तरह यूपीनेडा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन के लिए एक लाख, सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रशिक्षण (सूर्यमित्र) के लिए 12 करोड़, अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के लिए 15.75 करोड़ और यूटिलिटी स्केन बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

20 करोड़ मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के लिए और मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा के लिए दस करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई।

18 करोड़ रुपये झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना पर होंगे खर्च।

बजट वजन और विजन वाला

योगी सरकार ने विजन और वजन वाला बजट पेश किया है। बजट निवेश व रोजगार के लिए हेल्दी टॉनिक साबित होगा। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तीकरण का खाका खींचा गया है। यह प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का ब्लूप्रिंट है। हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन भी है और विकास का मन भी है। – **नंदगोपाल गुप्ता नंदी**, औद्योगिक विकास मंत्री